

दि का र्मिक पोस्ट

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 12, अंक : 33

(प्रति बुधवार),

इन्दौर, 12 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

भारत का ई-सफर-जम्मू-कश्मीर के वायु प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सबसे अधिक हिस्सेदारी



नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पिछले एक साल यानी अगस्त 2025 से जुलाई 2026 तक किसी भी महीने एक्ज्यूआई अच्छी श्रेणी में नहीं था क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हवा की गुणवत्ता सबसे अधिक खराब रही 2026 में पंजीकृत 1.40 लाख वाहनों में 1.07 लाख से अधिक वाहन पेट्रोल पर चलने वाले थे जबकि करीब 20 हजार वाहन डीजल चालित थे प्रदूषण के कारण राज्य में सांसों की बीमारियों बढ़ रही हैं।

सीडी अस्पताल में इमरजेंसी पहुंचने वाले और भर्ती होने वाले मरीज बढ़े कुछ दशकों पहले तक अपनी साफ हवा और शुद्ध वातावरण के लिए चर्चित जम्मू-कश्मीर अब वायु प्रदूषण से अछूता नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह यह पर्वतीय क्षेत्र तेजी से प्रदूषण की जद में आ रहा है। श्रीनगर के खोनमोह क्षेत्र में इस साल के शुरुआती छह महीनों (जनवरी से जून) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्ज्यूआई) 100-200 के बीच रहा। यह एक्ज्यूआई की मॉडरेट श्रेणी है। नवंबर और दिसंबर 2025 में यहां एक्ज्यूआई क्रमशः 279 और 246 दर्ज किया गया जो खराब (पूअर) श्रेणी है। जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण कमिटी के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल के दौरान यानी अगस्त 2025 से जुलाई 2026 तक किसी भी महीने एक्ज्यूआई अच्छी (गुड) श्रेणी (0-50 एक्ज्यूआई) में नहीं था। यहां तक की सबसे साफ माने जाने वाले

मॉनसून के महीनों में वायु की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हवा की गुणवत्ता सबसे अधिक खराब रही। वहीं, कई मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर में परिवहन क्षेत्र वायु गुणवत्ता को खराब करने में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखता है। जानकारों के अनुसार, परिवहन क्षेत्र का वायु प्रदूषण में करीब 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। श्रीनगर के चेस्ट डिस्सीज अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ की बड़ी वजह वायु प्रदूषण जनित बीमारियां भी हैं श्रीनगर के चेस्ट डिस्सीज अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ की बड़ी वजह वायु प्रदूषण जनित बीमारियां भी हैं

श्रीनगर के डलगेट स्थित सीडी (चेस्ट डिस्सीज) हॉस्पिटल में लंबे समय तक श्वसन रोग विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थ रहे और वर्तमान में गौसिया स्थित सरकारी अस्पताल में सेवारत डॉक्टर फिरदौस मंजूर ने डाउन टू अर्थ को बताया कि पहले बायोमास जलाने से सबसे अधिक प्रदूषण होता था लेकिन वर्तमान में पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल इसमें सबसे अधिक योगदान दे रहा है। उनका कहना है कि वायु प्रदूषण में इजाफा होते ही अस्पताल की ओपीडी में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। सीडी अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 में 18,672 लोग इमरजेंसी में पहुंचे जिनकी संख्या 2023-24 में बढ़कर 32,133 पहुंच गई। इसी तरह आईपीडी (इन पैशेंट्स डिपार्टमेंट) में इस अवधि में मरीजों की संख्या 4,315 से बढ़कर 7,480 हो

गई। जानकार इस उछाल की अहम वजह के तौर पर वायु प्रदूषण को भी जिम्मेदार ठहराते हैं।

फिरदौस मंजूर के अनुसार, सांस हर समय चाहिए। इसी के साथ प्रदूषक भी सांस के साथ अंदर जा रहे हैं। कुछ प्रदूषक तो खून तक में पहुंच रहे हैं। वह इसके लिए सीधे तौर सड़कों पर बढ़ रहे वाहनों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि 1990 के दशक में हमारे मोहल्ले में कुल 2-3 कारें थीं, जबकि मौजूदा समय में हर घर में 2-3 वाहन हो गए हैं। वाहनों की बढ़ी भीड़ में डीजल वाहन सबसे अधिक हैं जो प्रदूषण के अहम स्रोत हैं।

जम्मू-कश्मीर में परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों के आंकड़ों पर नजर डालने पर पता चलता है कि यहां अब तक 26,64,696 वाहनों का पंजीकरण हुआ है। 2025 में पंजीकृत वाहनों की वृद्धि दर 6.07 प्रतिशत थी। यहां पंजीकृत वाहनों में सबसे अधिक हिस्सेदारी जम्मू की है जहां कुल 8.8 लाख वाहन हैं। दूसरा सबसे अहम शहर श्रीनगर है जहां 4.10 लाख वाहन पंजीकृत हैं। वाहन डैशबोर्ड के अनुसार, 2026 में अब तक 1.4 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। 2025 में 1.90 लाख, 2024 में 1.79 लाख, 2023 में 1.71 लाख और 2022 में 1.62 लाख वाहनों का जम्मू-कश्मीर में पंजीकरण हुआ। आंकड़ों के अनुसार, यहां की सड़कों पर हर महीने करीब 20 हजार वाहनों की संख्या बढ़ रही है। इन वाहनों में जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। उदाहरण के लिए 2026 में पंजीकृत 1.40 लाख वाहनों में 1.07 लाख से अधिक वाहन पेट्रोल पर चलने वाले थे जबकि करीब 20 हजार वाहन डीजल चालित थे। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10,396 ही रही। इनमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी तिपहिया वाहनों (ऑटो) की रही। जम्मू-कश्मीर में जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण में वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से

सेवानिवृत्त वैज्ञानिक एवं वर्तमान में वैली इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज (वीआईपीसीईसीसी) कंसल्टेंसी की संचालक मुताहरा आबिदा वहीद देवा ने डाउन टू अर्थ को बताया कि ठंड में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि चलने तक में मुश्किल होती है। मुताहरा के अनुसार, इस मौसम में हवा के साथ धूल मिल जाती है और ठहर सी जाती है। वह कहती हैं कि इस मौसम में श्रीनगर में एक्ज्यूआई 300-400 तक भी पहुंच जाता है जो सामान्य नहीं है। उनका कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी के कारण निजी वाहनों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है जो वायु प्रदूषण में 40-50 प्रतिशत तक अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक फैयाज अहमद डाउन टू अर्थ को बताते हैं कि वायु गुणवत्ता मौसम के अनुसार बदलती रहती है। नवंबर से इसमें वृद्धि होती है और पार्टिकुलेट मैटर ठहर जाता है। वह इसकी वजह श्रीनगर की कटोरानुमा स्थिति को बताते हैं। श्रीनगर में प्रदूषण की एक अन्य वजह वह यहां बाहर से आने वाले करीब 6-7 लाख वाहनों को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि जब वाहन चलते हैं तो हर जगह अपने प्रदूषण का असर छोड़ते हुए जाते हैं। जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार आंदोलन एवं क्लाइमेट एक्शन ग्रुप के संस्थापक राजा मुजफ्फर भट ने डाउन टू अर्थ को बताया कि वायु प्रदूषण न केवल हवा की गुणवत्ता खराब कर रहा है बल्कि जल प्रदूषण का भी कारण बन रहा है। वह बताते हैं कि तीन साल पहले उन्होंने पीर पंजाल ग्लेशियर का दौरा किया था और वहां बर्फ पर ब्लैक कार्बन की मोटी परत देखी थी। उनका कहना है कि ब्लैक कार्बन युक्त ग्लेशियर का यह पानी बड़ी आबादी पीने में इस्तेमाल करती है।

भारत का ई-सफर श्रीनगर में इलेक्ट्रिक बसों, ई-रिक्शा और ऑटो के भरोसे ई-ट्रांसपोर्ट

जम्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इलेक्ट्रिक वाहनों ने पिछले तीन-चार सालों में जोर तो पकड़ा है लेकिन यह अभी केवल इलेक्ट्रिक बसों, ई-रिक्शों और तिपहिया (श्री व्हीलर) वाहनों तक ही सीमित है। इलेक्ट्रिक कारों सड़कों पर न के बराबर ही दिखाई दे रही हैं। बैटरी चालित दोपहिया वाहनों की गति भी धीमी है।

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2023 से अब तक करीब 44,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है। जम्मू-कश्मीर में 2026 में जुलाई तक कुल 9,482 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है जिनमें सर्वाधिक 6,186 तिपहिया वाहन शामिल हैं। यानी पंजीकृत वाहनों में 65 प्रतिशत ही हिस्सेदारी तिपहिया वाहनों की है। इसी तरह 2025 में पंजीकृत 11,289 वाहनों में तिपहिया वाहनों की संख्या 7,970 और 2024 में पंजीकृत 13,210 वाहनों में 6,636 तिपहिया वाहन थे। हालांकि 2023 में कुल पंजीकृत वाहनों में सबसे अधिक हिस्सेदारी यात्री ई-रिक्शों की थी। इस साल कुल 9,750 पंजीकृत वाहनों में 5,033 ई रिक्शा थे। 2023 के बाद ई रिक्शा के पंजीकरण में लगातार गिरावट आती रही जबकि तिपहिया वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। श्रीनगर में पेरिस ऑटोमोबाइल में जनरल मैनेजर (जीएम) सैयद मुश्ताक तिपहिया वाहनों की बिक्री के पीछे 30 हजार की सब्सिडी को भी श्रेय देते हैं। हालांकि यह सब्सिडी अप्रैल 2026 से बंद है। उनका शोरूम पिछले तीन साल से इलेक्ट्रिक श्री व्हीलर बेच रहा है। 2023-24 में उनके शोरूम ने 342, 2024-25 में 556 और 2025-26 में 892 श्री व्हीलर की बिक्री कर चुके हैं। 2026 में अप्रैल से जुलाई तक 281 श्री व्हीलर बेच चुके हैं। सैयद मुश्ताक कहते हैं कि श्रीनगर में अब कोई नया पेट्रोल ऑटो नहीं खरीद रहा। सड़कों पर दिखने वाले अधिकांश श्री व्हीलर बैटरी चालित हैं।

परिवहन विभाग में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अवनी लवासा ने डाउन टू अर्थ को बताया कि सरकार का जोर भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर है। उनका कहना है कि सड़कों पर बहुत अधिक ई रिक्शा और श्री व्हीलर की जरूरत नहीं है क्योंकि उनसे कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। उनका कहना है कि श्री व्हीलर को मिलने वाली सब्सिडी असीमित नहीं थी। वह सब्सिडी खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार इन्हें रेगुलेट कर रही है। श्रीनगर में इलेक्ट्रिक कारों अभी स्थानीय लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रही हैं। यही वजह है कि यहां 2026 में अब तक केवल 486 कारों का ही पंजीकरण हुआ। इसके पहले के वर्षों में भी कोई खास पंजीकरण नहीं हुआ। 2025 में 458, 2024 में 271 और 2023 में केवल 166 इलेक्ट्रिक कारों ही यहां पंजीकृत हुईं। इसी तरह 2026 में 2314, 2025 में 1650, 2024 में 941 और 2023 में 236 मोटरसाइकल व स्कूटर का पंजीकरण हुआ। श्रीनगर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक अहम कड़ी स्मार्ट

सिटी प्रोजेक्ट के तहत चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें हैं। श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से 100 और जम्मू कश्मीर राज्य परिवहन निगम लिमिटेड की तरफ से 20 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। स्मार्ट सिटी की लाल रंग की बसें ग्रांस कॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट (जीसीसी) मॉडल पर चल रही हैं। यानी बसों को चलाने का संपूर्ण जिम्मा टाटा कंपनी के पास है। कंपनी पर बसों के रखरखाव, चार्जिंग, ड्राइवर की जिम्मेदारी है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड केवल कंडक्टर मुहैया कराती है। स्मार्ट सिटी के अर्बन आर्किटेक्ट सुहैब नक्शबंदी ने डाउन टू अर्थ को बताया कि हमने नवंबर 2022 से शहर में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं।

जीसीसी मॉडल की ये बसें सरकार ने नहीं खरीदी हैं बल्कि सेवा खरीदी है। आमतौर पर जब सरकार बसें खरीदती है तो कुछ समय बाद बसें सड़ जाती थीं। संचालन और मरम्मत के अभाव में लोगों को वह सुविधा नहीं मिल पाती थी जो उन्हें मिलनी चाहिए। इसलिए यह जीसीसी मॉडल बेहतर है। नक्शबंदी के अनुसार, हर सिटी बस को 200 किलोमीटर चलाने का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य पूरा न होने पर पेनल्टी लगाई जाती है। उनका कहना है कि बसों की मांग के विश्लेषण के आधार पर रूट तय किए गए हैं। स्मार्ट सिटी 45 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से कंपनी को भुगतान करती है। ये बसें श्रीनगर शहर से करीब 50-60 किलोमीटर की दूर के इलाकों को कवर करती हैं। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी की बसें लोगों में खासी लोकप्रिय हो रही हैं, खासकर महिलाओं में इनकी लोकप्रियता अधिक है क्योंकि उनके लिए यात्रा मुफ्त है। नक्शबंदी कहते हैं कि इन बसों में प्रतिदिन 35,000 लोग यात्रा कर रहे हैं। इनमें से करीब 20,000 संख्या महिलाओं की है। वह मानते हैं कि लोगों ने इन बसों को अपनाया है। बसों की संख्या बढ़ने पर लोगों की निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। स्मार्ट सिटी की बसों का सबसे अधिक इस्तेमाल छात्र कर रहे हैं। इन बसों का शुरुआत से इस्तेमाल कर रही 20 वर्षीय छात्रा राबिया अमीन ने डाउन टू अर्थ को बताया कि उनके घर के सभी सदस्य इन बसों में सफर करते हैं। ये बसें प्राइवेट बसों के मुकाबले जल्दी पहुंचा देती हैं, इसलिए सभी इसे प्राथमिकता देते हैं। साथ ही महिलाओं की फ्री यात्रा से पैसों की भी बचत होती है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि बसों में वह कभी-कभी असुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि बसों में अक्सर जेबकतरों का खतरा रहता है। उनका मानना है कि बसों का एक हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना चाहिए ताकि वे सुरक्षित महसूस करें।

देश का गौरव बढ़ाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल-2026 में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। भारतीय मुक्केबाजों ने बताया कि उनके लगातार शानदार प्रदर्शन से विरोधी टीमों में ऐसा दबाव बना कि कई खिलाड़ी भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले ही घबराने लगे थे।

राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें सात स्वर्ण पदक शामिल रहे। महिला मुक्केबाज साक्षी ने बताया कि भारतीय मुक्केबाजों के प्रदर्शन का विरोधियों पर काफी असर पड़ा। उन्होंने कहा कि कई खिलाड़ी भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर पहले से ही आशंकित थे और उन्हें लगता था कि शुरुआती मुकाबले में हार के साथ उनका पदक जीतने का सपना खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन से भी उनके अनुभव पूछे। लवलीना ने स्वर्ण पदक की उम्मीद के बावजूद रजत पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब दुनिया के मुक्केबाज निश्चित रूप से भारतीय खिलाड़ियों से सावधान रहते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने और देश से मिले समर्थन ने भारतीय मुक्केबाजों के आत्मविश्वास को काफी मजबूत किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कई युवा खिलाड़ी खेलो इंडिया कार्यक्रम से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू के भावुक क्षणों का भी जिक्र किया। मीराबाई ने बताया कि पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने का दर्द उनके मन में था। इसके बाद चार वर्षों तक चोट और पारिवारिक परेशानियों के बीच उन्होंने लगातार मेहनत की। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रमंडल खेलों में वह पोलिडियम पर खड़ी थीं, तिरंगा ऊपर उठ रहा था और राष्ट्रगान बज रहा था, तब वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं। प्रधानमंत्री ने उनकी उपलब्धि को व्यक्तिगत सफलता से आगे बताते हुए कहा कि मीराबाई की जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के युवाओं में खेल के प्रति नया उत्साह पैदा करती हैं।



पेड़ों की ऊंची डालियों तक पहुंचा प्लास्टिक का जहर, हाउलर बंदरों में मिले माइक्रोप्लास्टिक के सबूत

नई दिल्ली। जंगल का वह हिस्सा जो जमीन से बहुत ऊपर, ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर बसता है, उसे हमेशा शहरी कचरे, सड़कों के किनारे पड़े प्लास्टिक और जलती पॉलिथीन के धुएं से दूर माना जाता था। लेकिन प्रकृति का यह सुरक्षित आशियाना भी अब इंसानी लापरवाही से अछूता नहीं रहा। वैज्ञानिकों को मैक्सिको के एक संरक्षित जंगल में विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके मेक्सिकन हाउलर बंदरों में माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। रिसर्च में इन बंदरों के मल के 66 में से 90 फीसदी से अधिक नमूनों में प्लास्टिक के बेहद बारीक कण मिले हैं।



गौरतलब है कि ये बंदर अपना अधिकांश समय पेड़ों की ऊंची डालियों पर बिताते हैं और मुख्य रूप से पत्तियां और फल खाते हैं। यानी प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल समुद्र, नदियों और जमीन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जंगल की ऊंची छतरी तक पहुंच चुका है। यह अध्ययन मैक्सिको के वेराक्रूज स्थित लॉस टुक्स्टलास बायोस्फीयर रिजर्व में किया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक, अमेरिका महाद्वीप में किसी संकटग्रस्त प्राइमेट में माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क का यह अब तक का सबसे पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण है। बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बेहद छोटे टुकड़े, रेशे या कण होते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि वे आसानी से दिखाई नहीं देते। हालांकि हवा, पानी और मिट्टी के साथ ये लंबी दूरी तक पहुंच सकते हैं। वहीं हाउलर बंदरों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा पेड़ों पर ही गुजरता है। उनकी लंबी, पकड़ बनाने वाली पूंछ और पेड़ों पर रहने की आदत उसे जमीन से काफी दूर रखती है। इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि शायद यह जीवनशैली उन्हें जमीन के

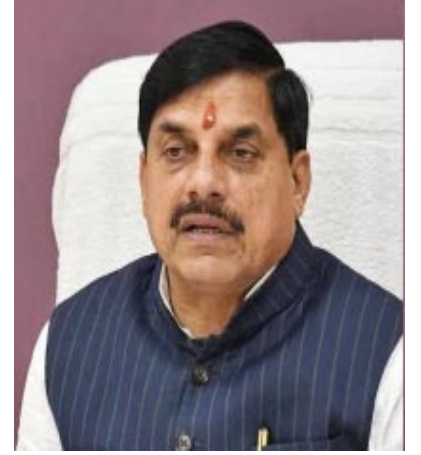
आसपास मौजूद प्रदूषण से कुछ हद तक बचाती होगी। लेकिन जो निष्कर्ष सामने आए हैं वे बिल्कुल इसके उलट हैं। शोधकर्ता मारिया फर्नांडा अल्वारेज-वेलास्केज और उनकी टीम ने बिना बंदरों को पकड़े उनके मल के नमूने एकत्र किए। प्रयोगशाला में एटीआर-एफटीआईआर नामक इन्फ्रारेड तकनीक से इन कणों की पहचान की गई। यह तकनीक किसी पदार्थ की रासायनिक पहचान बताती है, जिससे यह पुष्टि करने में मदद मिलती है कि मिला हुआ कण वास्तव में प्लास्टिक है या मिट्टी, पौधे अथवा कोई अन्य पदार्थ। जांच में 66 नमूनों में से 90 फीसदी से अधिक में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी की पुष्टि हुई। वैज्ञानिकों ने इसमें प्लास्टिक के 31 अलग-अलग प्रकार के पॉलिमर की पहचान की है। इनमें पॉलीएथिलीन सबसे अधिक पाया गया। स्टडी में कुछ ऐसे प्लास्टिक भी मिले, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर पेय पदार्थों की बोतलों और पैकेजिंग में होता है। इनमें पीईटी भी शामिल था। प्लास्टिक के कुछ प्रकारों को अध्ययन में रासायनिक खतरे से जुड़ी श्रेणियों में रखा गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि बंदरों को प्लास्टिक से कोई बीमारी हो रही है। इनके मल में माइक्रोप्लास्टिक का मिलना यह बताता है कि बंदर इनके संपर्क में आए और संभवतः इन्हें निगल गए। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ये कण उनके शरीर के अंगों में जमा हो गए हैं या बीमारी पैदा कर रहे हैं। इस अध्ययन में सामने आया सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्लास्टिक के ये कण पेड़ों की इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। शोधकर्ताओं का इस बारे में अनुमान है कि हवा माइक्रोप्लास्टिक को दूर-दराज तक ले जा सकती है। ये कण पेड़ों की पत्तियों और फलों पर जम सकते हैं और भोजन करते समय बंदरों के शरीर में पहुंच सकते हैं। साथ ही बारिश भी इन कणों को पेड़ों की सतह या पानी के छोटे

स्रोतों तक पहुंचा सकती है। बंदरों का एक-दूसरे की सफाई करना यानी ग्रूमिंग भी एक संभावित रास्ता हो सकता है। जहां फर पर चिपके प्लास्टिक के कण मुंह तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही सांसों के जरिए भी माइक्रोप्लास्टिक के शरीर में जाने की आशंका है। हालांकि मौजूदा अध्ययन इन सभी रास्तों में से किसी एक को निश्चित रूप से साबित नहीं करता। यानी जंगल की ऊंची छतरी शायद हवा में तैरते प्रदूषण को रोक नहीं पाती। जो प्लास्टिक जमीन से उड़ता है, वह पत्तियों पर बैठ सकता है और फिर उसी पत्ती या फल के साथ बंदर के पेट तक पहुंच सकता है। देखा जाए तो यह खोज पूरी तरह अप्रत्याशित भी नहीं है। इससे पहले सितंबर 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन में ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में रहने वाले दो रेड हाउलर बंदरों के पेट में हरे रंग के प्लास्टिक रेशे पाए गए थे। मैक्सिको का नया अध्ययन इससे आगे जाता है, क्योंकि इसमें अधिक संख्या में नमूने लिए गए और प्लास्टिक की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला तकनीक का इस्तेमाल किया गया। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में जंगल के आसपास के कचरे के स्रोतों पर भी ध्यान दिया है। प्लास्टिक की बोतलें, पैकेजिंग, बैग और अन्य कचरा अगर खुले में फेंका या जलाया जाए तो उसके छोटे कण हवा में फैल सकते हैं। हवा इन कणों को जंगल की ओर ले जा सकती है। वहां वे पत्तियों, फलों और पानी पर जमा हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी किसी एक स्रोत को माइक्रोप्लास्टिक का निश्चित कारण नहीं बताया है। जंगल के आसपास का कचरा, सिंथेटिक फाइबर, खुले में कचरा जलाना और दूर से आने वाला वायु प्रदूषण, इन सभी की इसमें भूमिका हो सकती है। मैक्सिकन हाउलर बंदर पहले ही अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जंगलों का खतम होना और उनका छोटे-छोटे हिस्सों में बंट जाना है। शिकार और अन्य मानवीय दबाव भी इनके लिए खतरा बन रहे हैं।

जलवायु संकट के दौर में नए सिरे से समझना होगा जीवन रक्षा का अर्थशास्त्र

बैठकों के लिए यूरोप में थी और वहां भीषण गर्मी पड़ रही थी। भारतीय होने के नाते मैं गर्मी की आदी हूं मगर वहां चिलचिलाती धूप महसूस हो रही थी। यह भी स्पष्ट था कि ये देश गर्मी के लिए नहीं बने हैं, जो इमारतों से लेकर तापमान नियंत्रण उपकरणों तक सभी से जाहिर हो रहा था। जब मैं स्वदेश लौट रही थी तब पूरे भारत में मॉनसून कहर बरपा रहा था। आर्थिक राजधानी मुंबई बाढ़ के पानी से त्रस्त हो गई थी, सड़कों पर पानी ही पानी था, जो घरों में भी घुस गया था। हिमालय और पश्चिमी घाट में बादल फटने से भूस्खलन और संपत्ति का नुकसान हो रहा था। सड़कों और पुलों को नुकसान होने की खबरें भी आ रही थीं, जिनमें कुछ तो हाल ही में बने थे। इससे पता चल रहा था कि निवेश करते समय जलवायु की चरम स्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया था। और यह सब केवल एक सप्ताह के भीतर घटित हुआ। इसके बाद भी अगर कोई जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठा रहा है तो वह सच्चाई से आंखें मूंद रहा है और भ्रम में जी रहा है। तापमान में तेज वृद्धि और मौसम में अचानक बदलावों की भविष्यवाणी जलवायु परिवर्तन के मॉडल ने पहले ही कर दी थी। अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अपने ग्रह को प्रभावित करने वाले इस विनाशकारी प्रभाव को रोकने के लिए हम बहुत कम प्रयास कर रहे हैं। अब हमें साथ मिलकर काम करना होगा। दुख की बात है कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं जू न केवल कार्यों में बल्कि उस सोच में भी जो दुनिया को बेहतर जगह बना सकती है। हकीकत यह है कि देशों में हरित प्रौद्योगिकी जलवायु परिवर्तन कम करने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा और आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होने के कारण पैठ बना रही है। जीवाश्म ईंधन का सहारा लिए बिना सौर ऊर्जा की ओर बढ़ना तभी कारगर होता है, जब पैनल और बैटरियां बिजली का ग्रिड लगाने और बनाने से सस्ती पड़ेंगी। देश अपनी घरेलू प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय ले रहे हैं और साथ में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी घट रहा है।

कम वर्षा की स्थिति में प्रत्येक जिले में आवश्यक तैयारी रखी जाए - मुख्यमंत्री डॉ. यादव



इंदौर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इस मानसून में प्रदेश में औसत से 15 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। कुछ जिलों में वर्षा कम हुई है और कुछ जिलों में आने वाले समय में अधिक वर्षा की संभावना है। वर्तमान में प्रदेश के आधे जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। ऐसी असामान्य स्थितियों में किसानों सहित नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय भोपाल में प्रदेश में कम वर्षा की वर्तमान स्थिति और उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में मंत्री गण और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुछ जिलों में कम वर्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में कम वर्षा के कारण उत्पन्न हालातों से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां संबंधित विभाग सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जानकारी दी गई कि प्रदेश में 1 जून से 10 अगस्त की अवधि में सामान्य वर्षा 571 मिली मीटर की तुलना में 483 मिली मीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है जो औसतन 15 प्रतिशत कम है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पूर्वी मध्यप्रदेश में 513.20 मिलीमीटर और पश्चिम मध्यप्रदेश में 459.80 मिलीमीटर वर्षा हुई है। प्रदेश की कुल औसत वर्षा 949. 50 मि.मी. है। जहां तक फसलों की

बोवनी का प्रश्न है प्रदेश में धान की 84 प्रतिशत बोवनी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि एहतियातन आने वाली रबी फसलों के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए जिससे कम सिंचाई में उगाई जाने वाली फसलों को प्राथमिकता से ले सकें। विशेष रूप से चने की फसल के लिए आवश्यक बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राज्य और जिला स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम संचालित रहे जहां जल भराव और क्षति से जुड़ी सूचनाओं को तुरंत दर्ज किया जाए और जल भराव या बाढ़ संभावित क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आकलन किया जाए। वर्षा काल में होने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम भी आवश्यक है। इसके लिए औषधियों पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों। प्रत्येक जिले में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अतिवृष्टि या जल भराव से प्रभावित फसलों का राजस्व विभाग के दलों द्वारा पारदर्शिता से सर्वेक्षण हो। क्षति का सर्वेक्षण हो और किसानों को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, सामाजिक न्याय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके भी उपस्थित थीं। अन्य मंत्रीगण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कृषि मंत्री श्री एन्दल सिंह कंधाना बैठक से वर्चुअल रूप से जुड़े। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, पुलिस महानिदेशक श्री

कैलाश मकवाणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के बांधों में 10 अगस्त तक जलभराव की स्थिति लगभग 49 प्रतिशत है, जो औसत से 10 प्रतिशत कम है। गत 5 वर्ष में 59 प्रतिशत औसत जल भराव की स्थिति रही है। गत वर्ष जल भराव की स्थिति 75 प्रतिशत थी। ऐसे जलाशय जिनमें जल भराव 50 प्रतिशत या उससे कम है उनकी संख्या 36 है। प्रदेश के ऐसे जलाशय जिनमें जलभराव 50 से 90 प्रतिशत कम है उनकी संख्या 18 है।

प्रदेश के बुनकर, शिल्पकार और कलाकारों की समृद्धि के लिए सदैव तत्पर सरकार

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन उद्योगों से जुड़े भारत के सभी बुनकरों, शिल्पकारों, मूर्तिकारों और अन्य कलाकारों के परिश्रम को पूरा सम्मान दिलाने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिये सभी परिश्रमी किसानों, हुनरमंद बुनकरों, समर्पित शिल्पियों और बेहतरीन ग्रामीण कलाकारों को सम्मानित करने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई कलाकार हुए हैं, जिन्होंने मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को विश्व पटल पर सुशोभित किया है।

हमारी सरकार सभी कलाकारों की समृद्धि के लिए सदैव तत्पर है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने %वोकल फॉर लोकल% और %लोकल टू ग्लोबल% का महामंत्र दिया है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के इसी महामंत्र के अनुसार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में हाथकरघा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित बुनकरों एवं शिल्पियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की हाथकरघा और हस्तशिल्प परम्परा को समृद्ध करने वाले प्रदेश के 15 श्रेष्ठ शिल्पियों और बुनकर को विभिन्न पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित कर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर इस बुनकर-शिल्पी सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने बुनकर-हस्तशिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं मिट्टी से शिवलिंग (पिंडी) भी बनाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तैयार किए गए 2 वेब कॉमर्स पोर्टल - मृगनयनी) और ओडीओपी मार्ट एमपी नामक ई-कॉमर्स पोर्टल्स का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी बुनकरों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से जुड़े कलाकारों और विशेष तौर पर ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए 2 ई-कॉमर्स वेब पोर्टल्स की शुरुआत की गई है। इसी पोर्टल को देश में पहला पुरस्कार मिला है। यह राज्य सरकार और कुटीर एवं ग्रामोद्योग

विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है। ई-कॉमर्स पोर्टल से मृगनयनी इंफोरियम के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी देश के 16 हजार से अधिक स्थानों पर सुनिश्चित हो रही है। पहले चरण में मृगनयनी पोर्टल पर 460 से अधिक उत्पाद पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदेरी का कुर्ता, महेश्वर की साड़ी, बाग की शॉल और जरी का बैग सभी वस्तुएं प्रदेशवासियों को गौरव का अनुभव कराती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों के अथक परिश्रम से उपजे से बुनकर कपड़ा, बुटिक और खादी तैयार करते हैं। खादी मध्यप्रदेश की विशेष पहचान रही है। मध्यप्रदेश आज सभी क्षेत्रों में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हाथकरघा और शिल्पकला को प्रोत्साहन पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। वे अपने खून-पसीने और अथक परिश्रम से समृद्ध परंपरा और कला को संरक्षित करते हुए आगे कर रहे हैं। शिल्पकार और कलाकारों के हाथों में चमत्कारिक प्रतिभा होती है। उन्होंने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 250 वर्ष पूर्व महेश्वरी साड़ी के माध्यम से देशभर के बुनकरों को संरक्षण प्रदान किया। चंदेरी, इंदौर और उज्जैन प्रत्येक शहर में बुनकर और शिल्प कलाकारों को अनेक अवसर मिल रहे हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी भी अब कुटीर एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को अपना रही है। अब भोपाल और इंदौर के प्रमुख बाजारों में ये उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। अब नए पोर्टल्स के शुभारंभ से यह उत्पाद ऑनलाइन शॉपिंग के लिए युवाओं के लिए उपलब्ध होंगे। ओडीओपी उत्पादों में भी हम चंदेरी की साड़ी, सीधी की दरी, उज्जैन का बटिक, धार का बाग प्रिंट को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश के 7 जिलों के कारीगरों द्वारा निर्मित 2 हजार से अधिक उत्पादों की देशभर में आपूर्ति की जा रही है। बाजार में इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सरकार साथ है।